रफाल सौदाः खुद मोदी कटघरे में

रफाल सौदे ने मोदी राज में पल रहे भ्रष्टाचार और दरबारी पूंजीवाद पर पड़े पर्दे को चीरकर रख दिया है। इतना ही नहीं, 126 रफाल लड़ाकू विमानों के पहले सौदे को रद्द किए जाने और उसकी जगह पर सीधे उड़ान भरने के लिए तैयार 36 विमानों का आर्डर दिए जाने तक का जो घटनाक्रम सामने आया है, उसने इस ताजातरीन रक्षा घोटाले में सीधे खुद प्रधानमंत्री का हाथ होने का सच सामने ला दिया है।

पिछले सप्ताह फ्रांस के पूर्व- राष्ट्रपति, फ्रांस्वा ओलांद के जो बयान आए हैं, उन्होंने मोदी सरकार की पर्दापोशी की कोशिशों और उसके झूठ को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है।

> एएफपी की रिपोर्ट ओलांद को उद्घृत करती है: *'रिलायंस ग्रुप का नाम, रफाल सौदे की वार्ताओं में एक ''नये फार्मूले'' के हिस्से के तौर पर आया था, जिसे मोदी सरकार ने तय किया था।'*

ओलांद उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति थे, जब रफाल समझौते पर दस्तखत हुए थे। उन्होंने एक फ्रांसीसी वैबसाइट से साक्षात्कार में बताया कि रफाल सौदे के लिए भारतीय साझीदार के नाम का प्रस्ताव भारत सरकार की ओर से आया था और इस मामले में फ्रांस की सरकार या लड़ाकू विमान निर्माता कंपनी दॅसां के हाथ में कुछ था ही नहीं। उन्होंने दो-टूक शब्दों में कहा: 'इस मामले में हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं था।'

अगले ही दिन, 22 सितंबर को प्रांसीसी समाचार एजेंसी *एएफपी* के साथ बात करते हुए, ओलांद ने अपनी बात और साफ कर दी। *एएफपी* की रिपोर्ट के अनुसार, 'ओलांद ने कहा कि रिलायंस का नाम, रफाल सौदे की वार्ताओं में एक ''नये फार्मूले'' के हिस्से के तौर पर आया था, जो सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने तय किया था।'

इससे रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामण द्वारा अपनाया गया रुख पूरी तरह से झूठा साबित हो जाता है। वह चंद रोज पहले तक इसी के दावे कर रही थीं कि दॅसां द्वारा चुने गए भारतीय साझेदार के संबंध में सरकार को कुछ पता ही नहीं था और उक्त निर्णय में

सरकार की कोई भूमिका ही नहीं थी।

यहां यह याद दिलाना उपयोगी होगा कि भारत के ऑफसैट्स साझीदार का फैसला क्यों इस सौदे में घोटाले के साक्ष्यों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। 2012 में एक खुली हुई टेंडर मूल्यांकन प्रक्रिया के जरिए, भारतीय वायु सेना के लिए 126 लड़ाकू जैट विमानों की खरीद के लिए, दॅसां द्वारा निर्मित रफाल लड़ाकू विमानों का चुनाव किया गया था। इसके लिए हुए करारनामे में इसका प्रावधान किया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लि0 (एचएएल) द्वारा दॅसां की साझेदारी में, 108 रफाल लड़ाकू विमानों का भारत में ही उत्पादन किया जाएगा। तब तक 18 लड़ाकू विमान ही सीधे उड़ान भरने की स्थिति में आने वाले थे।

बहरहाल, 2015 के अप्रैल में जब प्रधानमंत्री मोदी पेरिस गए, 126 विमानों के पहले वाले करार को ही रद्द कर दिया गया और दॅसां के साथ एक नये करार पर दस्तखत कर दिए गए। यह करार 36 रफाल विमानों की सीधे उड़ान भरने की स्थिति में आपूर्ति के लिए था। इसके साथ ही साथ, विदेशी खरीद के ऐसे सौदों की कीमत के 50 फीसद की स्थानीय रूप से खरीद के ऑफसैट्स के प्रावधान को पूरा करने के लिए, करीब 21,000 करोड़ रु0 के ठेकों के लिए मुख्य भारतीय साझीदार के रूप में, अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को चुन लिया गया।

मूल सौदे को, जो बोलियां आमंत्रित किए जाने तथा भारतीय वायु सेना द्वारा आकलन की लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद हुआ था, रद्द क्यों कर दिया गया, इस सवाल का संतोषजनक जवाब कभी नहीं दिया गया। इस में भी किसी विवाद की गुंजाइश नहीं थी कि भारतीय वायु सेना को 126 विमानों की जरूरत थी क्योंकि उसकी विमान शक्ति, 42 स्क्वैड्रन की वांछित संख्या से काफी कम रह गयी थी।

मोदी सरकार और खासतौर पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन तथा वित्त मंत्री अरुण जेटली, यह कहकर मुद्दे को धुंधलाने की ही कोशिश करते रहे हैं कि कीमत पर और एचएएल के साथ सह-उत्पादन के समझौते पर वार्ताओं में प्रगति नहीं हो रही थी। निर्मला सीतारमन ने एक साक्षात्कार में यह भी कहा था कि एचएएल में ढांचागत सुविधाओं के अभाव के कारण ही दॅसां का उससे समझौता नहीं हो पाया था।

लेकिन, जल्द ही यह झूठ पूरी तरह से बेनकाब हो गया। पिछले ही दिनों एचएएल के पूर्व-अध्यक्ष टी सुवर्ण राजू ने, जो 1 सितंबर 2018 को ही सेवानिवृत्त हुए थे, एचएएल में इस काम के लिए जरूरी क्षमता न होने के दावे का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा: 'जब एचएएल कच्चे माल के चरण से लगाकर, 30 टन सुखाई-30 विमान का निर्माण

कर सकता है, जो कि एक चौथी पीढ़ी का लड़ाकू जैट है, जो वायु सेना की मुख्य ताकत है, तो हम किस के बारे में बात कर रहे हैं। बेशक हम कर देते (लाइसेंस के आधार पर राफाल का उत्पादन कर देते।)'

उन्होंने इस झूठ को भी बेनकाब कर दिया है कि दॅसां के साथ कोई समझौता ही नहीं हुआ था। 'दोस्सां और एचएएल ने एक परस्पर कार्य-साझेदारी समझौते पर दस्तखत किए थे और उसे सरकार को सौंप दिया था। आप सरकार से क्यों नहीं कहते कि इस फाइल को सार्वजनिक कर दे? फाइलें खुद ही सब कुछ बता देंगी।'

एचएएल के पूर्व-मुखिया की इस बात के सच होने की पुष्टि, खुद दोस्सां के सीईओ, एरिक ट्रेप्पिअर के एक संवाददाता सम्मेलन के रिकार्ड से हो जाती है। मोदी की पेरिस यात्रा से सिर्फ दो सप्ताह पहले, ट्रेप्पियर ने कहा था कि सौदा '95 फीसद पूरा' हो चुका था और एचएएल के साथ कार्य-साझेदारी समझौते पर दस्तखत हो चुके थे।

इसी मुकाम पर दरबारी पूंजीवाद का प्रवेश होता है। अनिल अंबानी की कंपनी, रिलायंस डिफेंस का रक्षा उत्पादन का कोई अनुभव ही नहीं है। सच तो यह है कि अनिल अंबानी के ग्रुप की कई कंपनियां भारी कर्जे में डूबी हुई हैं। तब यह चमत्कार कैसे हुआ कि ऐसी कंपनी को, एक उन्नत लड़ाकू जैट के लिए, बहुत ही जटिल उपकरण बनाने का काम थमा दिया गया।

यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे खुद ही दखल देते हैं। 2016 के अप्रैल में मोदी एक सरकारी यात्रा पर फ्रांस गए थे। उनकी इस सरकारी यात्रा से पहले सरकार में या भारतीय वायु सेना में, किसी भी स्तर पर इस पर कोई विचार नहीं हुआ था कि दॅसां के साथ 126 विमानों की खरीद के समझौते को रद्द कर देना चाहिए और इससे काफी कम संख्या में विमानों की खरीद के लिए उसी कंपनी के साथ, नया समझौता किया जाना चाहिए। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति को इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। तब के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को भी, मोदी के पेरिस के लिए रवाना होने के चंद घंटे पहले ही इस फैसले की जानकारी दी गयी थी।

इस तरह प्रधानमंत्री ने फ्रांस की यात्रा की और इस यात्रा में उनके साथ गए लोगों में, अनिल अंबानी भी शामिल थे। इस आशय की एक खबर मौजूद है कि नये समझौते के एलान के बाद, अनिल अंबानी ने दॅसां के सीईओ से बातचीत की थी। इसलिए, यह मानने के तमाम कारण मौजूद हैं कि मोदी के कहने पर ही फ्रांसीसी कंपनी ने अनिल अंबानी के साथ समझौता करने का फैसला लिया था।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एचएएल की जगह पर, एक निजी कंपनी को बैठाया जाना वैसे भी, रक्षा उत्पादन के निजीकरण की मोदी सरकार की मुहिम के साथ फिट बैठता है। फिर भी, इस काम के लिए एक सरासर अयोग्य कंपनी का चुना जाना, निश्चित रूप से किसी लेन-देन की ओर इशारा करता है।

इतना ही नहीं, नये सौदे में रफाल लड़ाकू विमान की कीमत, पहले के समझौते में स्वीकार की गयी कीमत से दोगुनी बैठती है। इसी सचाई को छुपाने के लिए मोदी सरकार संसद को इन विमानों की कीमत का ब्यौरा देने से हठपूर्वक इंकार करती आयी है।

कुछ टिप्पणीकार यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक इस सौदे में पैसे के लेन-देन के कोई साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। लेकिन, इस बात को इस तथ्य की रौशनी में देखा जाना चाहिए कि मोदी के भारत में किस तरह से ऊंचे स्तर के भ्रष्टाचार को वैधता प्रदान कर दी गयी है। अब किसी भी सौदे के लिए घूस का पैसा पूरी तरह से कानूनी तरीके से, चुनावी बांडों के जरिए दिया जा सकता है, जिसके संबंध में कोई सवाल ही नहीं किए जा सकते हैं।

इसके आलावा प्रधानमंत्री के इस मनमाने कदम से राष्ट्रीय सुरक्षा को हुए नुकसान का और बड़ा मुद्दा भी है। वायु सेना को लड़ाकू जैट विमानों के स्क्वैड्रनों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था। इस संबंध में पहला प्रस्ताव का अनुरोध (आरएफपी) 2007 में, यूपीए सरकार के समय में जारी किया गया था। इसके बाद, बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया के जरिए उपयुक्त लड़ाकू विमान की निशानदेही की गयी थी और 2012 में 216 रफाल लड़ाकू विमानों के लिए समझौता हुआ था।

लेकिन, इस समझौते के पालन की प्रक्रिया को तेज करने के बजाए, मोदी ने इस समझौते को ही निरस्त कर दिया। इसकी जगह पर 36 राफाल लड़ाकू विमानों यानी दो स्क्वैड्रन के लिए ही सौदा किया गया, जो किसी भी तरह से वायु सेना की जरूरतों को पूरा नहीं करता है। इतना ही नहीं, इन विमानों को तैयारशुदा स्थिति में खरीदा जाना है, जिसके चलते इस सौदे में कोई प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी नहीं होने जा रहा है। इस सब के ऊपर से वायु सेना ने अब सरकार से नये सिरे से 110 लड़ाकू विमान खरीदने का अनुरोध किया है। इस तरह, समूची प्रक्रिया में एक दशक से ज्यादा की देरी हो चुकी है।

इसलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में एक नहीं दो-दो अपराधों के दोषी हैं। एक तो उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया है। दूसरे उन्होंने भ्रष्टाचार तथा दरबारी पूंजीवाद को पाला-पोसा है। स्वतंत्र जांच हो तो वह कटघरे में खड़े पाए जाएंगे।

रफाल घोटाला क्या है?

मुहावरे में जिसे प्याज के छिलके कहते हैं, रफाल घोटाला कुछ उसी तरह का है। इसकी एक परत उतारिए, उसके नीचे अगली परत छिपी निकलेगी। और जैसे-जैसे आप प्याज की परतें छीलेंगे, उसकी झल से आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस घोटाले की जो एकदम नयी परत उतरी है, वह फ्रांस के पूर्व-राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के बयान से उतरी है। ओलांद ने ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ रफाल सौदे पर दस्तखत किए थे।

भारत के इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री ने सीधे खुद हस्तक्षेप कर, पहले तय हो चुके किसी प्रतिरक्षा सौदे को निरस्त कर दिया हो और वह भी दूसरे ऐसे किसी भी अधिकारी से कोई परामर्श तक किए बिना, जिन पर यह तय करने का जिम्मा है कि देश की सुरक्षा के लिए किस तरह के हथियारों तथा साज-सामान की जरूरत है। इस मामले में वायु सेना तक से नहीं पूछा गया। इससे पहले हमारे देश में इतनी बेशर्मी से दरबारी पूंजीवाद को आगे भी नहीं बढ़ाया गया था, जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सौदे में अनिल अंबानी की कंपनी के मामले में किया गया है।

इस मामले में जवाबदेही प्रधानमंत्री से शुरू होकर, उन पर ही खत्म हो जाती है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से और सीधे, खुद ही फैसला लिया था।

इसके ऊपर से रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमण हैं जिन्हें झूठ बोलने में और सार्वजनिक क्षेत्र की एक नवरत्न कंपनी को बदनाम करने में भी कोई हिचक नहीं हुई है। और उन्होंने ऐसा कोई देश की हिमायत में नहीं बल्कि अपने नेता के बचाव के लिए किया है।

इस प्रश्नोत्तरी के जरिए हमने इस घोटाले के जरूरी विवरण पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस विवरण से उठने वाले प्रश्न, सी पी आइ (एम) समेत अनेक विपक्षी पार्टियों की इस मांग के सहीपन की पुष्टि करते हैं कि एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए ताकि इस सौदे की और उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका की जांच की जा सके।

मूल रफाल सौदा क्या था ?

रफाल, फ्रांस की दॅसां एविएशन कंपनी का बनाया उन्नत लड़ाकू विमान है। 6 प्रतिस्पर्द्धी लड़ाकू विमानों के एक दशक लंबे मूल्यांकन के बाद, भारत ने इस विमान को खरीदने का फैसला लिया था। इससे पहले इस देश में बोफोर्स समेत कई रक्षा खरीद घोटाले हो चुके थे और इसकी पृष्ठभूमि में यह फैसला खुली टेंडर की प्रक्रिया के जरिए लिया गया था।

रक्षा मंत्रालय ने 126 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 2004 में एक खुले टेंडर की शुरूआत की।

126 मल्टी रोल कांबैट एअरक्राफ्ट्स (एमआरसीए) के लिए टेंडर की प्रक्रिया (रिक्वेस्ट फॉर इन्फार्मेशन–आरएफआइ) 2004 में शुरू की गयी थी। बाद में इसे संशोधित कर मीडियम वेट मल्टी रोल कांबैट एअरक्राफ्ट (एमएमआरसीए) तक सीमित कर दिया गया। इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरपीएफ) को 2007 में जारी किया गया।

भारतीय विमान सेना ने विमानों की यह संख्या तय की थी। अपने अलग-अलग किस्म के विमानों के मिश्रण और आने वाले समय में पुराने मिग विमानों के सेवा से बाहर होने को हिसाब में लेते हुए, बहुत सोच-विचार कर 126 (7 स्क्वैड्रन) विमानों की अपनी जरूरत तय की थी। आगे आ रहे घरेलू तेजस हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) और रूसी मूल के सुखोई-30 के साथ, इन 126 विमानों के जुड़ने से, भारतीय वायु सेना को हल्के, मंझले तथा भारी लड़ाकू विमानों का एक मजबूत, संतुलित तथा सुसज्जित बेड़ा हासिल हो गया होता।

भारतीय वायु सेना ने 126 लड़ाकू विमान हासिल करने का फैसला लिया था, ताकि एक मजबूत तथा संतुलित जहाजी बेड़ा खड़ा कर सके।

भारत में विस्तृत मैदानी परीक्षणों के बाद और विमानों की जीवन चक्र (पूरे जीवन काल) की कीमतों की तुलना करने के बाद, 2012 में रफाल विमान का अंतिम रूप से चुनाव हो गया। टेंडर के अनुसार, इनमें से पहले 18 विमान ही सीधे-सीधे तैयारशुदा स्थिति में खरीदे जाने थे। शेष 108 विमानों का भारत में ही रक्षा क्षेत्र की नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी, हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लि0 (एचएएल) द्वारा, दॅसां से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अंतर्गत उत्पादन किया जाना था। इस तरह, भारत को सिर्फ ये लड़ाकू विमान ही नहीं मिलने थे बल्कि उसे इन विमानों के निर्माण की उन्नत प्रौद्योगिकी भी मिलनी थी, जिसका उपयोग आगे चलकर देसी विमानों के विकास में या अन्य उद्योगों में भी होता। भारत शुरू से यही रास्ता अपनाता आया था—विनिर्माण में देसीकरण तथा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाओ।

2012 में दॅसां के रफाल का चयन किया गया, जिसका भारतीय साझेदार एचएएल को बनाया गया।

मोदी का रफाल सौदा क्या है ?

रफाल सौदा करीब-करीब अपनी अंतिम मंजिल पर था। तभी 2015 के अप्रैल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा के दौरान और बिना कोई कारण बताए, इस सौदे को रद्द कर दिया गया। फ्रांस के तत्कालीन प्रधानमंत्री, फ्रांस्वा ओलांद के साथ बातचीत में मोदी ने तय किया कि 126 विमानों के मूल रफाल सौदे की जगह पर, 36 रफाल विमानों की सीधे-सीधे खरीद के दो सरकारों के बीच के सौदे को बैठा दिया जाए। ये छत्तीस के छत्तीस विमान, फ्रांसीसी कंपनी दॅसां द्वारा बनाए जाने थे। मोदी की इस पेरिस यात्रा के दौरान रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (रिलायंस एडीएजी) के अनिल अंबानी भी पेरिस में मौजूद थे। बाद में अंबानी की कंपनी दॅसां की आफॅसैट साझीदार बन गयी।

2015 के अप्रैल में मोदी 126 विमानों के पहले वाले सौदे को रद्द कर दिया और उसकी जगह पर 36 विमानों की सीधे खरीद का आदेश दे दिया।

जाहिर है कि अब जबकि सीधे उड़ने की स्थिति में कुल 36 विमान खरीदे जा रहे हैं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बाकी हरेक रक्षा सौदे की तरह इस सौदे में भी ऑफसैट्स होंगे तो सही, लेकिन रफाल विमान बनाने के लिए नहीं होंगे क्योंकि ये विमान तो पूरी तरह से तैयार होकर आएंगे। ये ऑफसैट्स फाल्कॉन

अब रफाल विमानों का घरेलू तौर पर कोई निर्माण ही नहीं होना था और एचएएल को हटाकर, अनिल अंबानी की रिलायंस को ऑफसैट्स के लिए साझीदार बना दिया गया।

लक्जरी एक्जिक्यूटिव जैट विमानों के लिए होंगे। ये विमान भी दॅसां ही बनाती है। इस तरह, घरेलू तौर पर उन्नत विमान बनाने और इससे जुड़ी उन्नत प्रौद्योगिकी हासिल करने तथा पचाने का एक शानदार मौका गंवा दिया गया। इस नये सौदे पर, 23 सितंबर 2016 को नई दिल्ली में भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। जो 36 विमान खरीदे जा रहे हैं, उनकी आपूर्ति 2019 के सितंबर/ अक्टूबर में शुरू होगी और 2022 के अप्रैल तक पूरी हो जाएगी।

कभी भी न तो प्रधानमंत्री ने और न ही रक्षा मंत्री ने इसकी कोई सफाई दी है कि खुले टेंडर की प्रक्रिया के जरिए, 126 विमान खरीदने की एक दशक लंबी प्रक्रिया को छोड़कर, सिर्फ 36 विमानों के लिए सीधे सौदा क्यों किया गया? इन विमानों की कीमत किस ने तय की? 36 विमान ही खरीदने का किसने फैसला लिया? इनमें से किसी भी सवाल का अब तक जवाब नहीं मिला है?

इसकी कोई सफाई नहीं दी गयी कि मूल टेंडर को क्यों रद्द किया गया और सीधी खरीद के बदनाम रास्ते को क्यों अपनाया गया।

सिर्फ 36 विमानों की इस खरीद से, भारतीय वायु सेना के बेड़े में एक बड़ा सा छेद छूट गया है। उसकी शक्ति स्क्वैड्रनों की आवश्यक संख्या से कम रह गयी है। रक्षा मंत्रालय अब 110 विमानों के लिए एक नये टेंडर की बात कर रहा है। तब पहले वाले सौदे को रद्द ही क्यों किया गया था? हम रक्षा उपकरणों की टुकड़ों-टुकड़ों में खरीद का वही बदनाम तरीका फिर क्यों अपना रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय अब 110 और विमानों की खरीद की योजना बना रहा है। यही करना था तो मूल टेंडर को रद्द ही क्यों किया गया?

मोदी का सौदा बहुत महंगा पड़ेगा

पहले के सौदे के अनुसार, 126 विमान 2015 के अप्रैल की रुपए की विनिमय दर पर, करीब 53,350 करोड़ रु0 के बैठने जा रहे थे यानी एक विमान करीब 423 करोड़ रु0 पड़ने वाला था। दूसरी ओर रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, सुभाष भामरे ने इसी साल के शुरू में संसद में यह बताया भी था कि नये सौदे में हरेक विमान की बुनियादी कीमत, 670 करोड़ रु0 बैठती है (फाइनेंशियल एक्सप्रैस, 12 मार्च 2018)। उसमें लगाए गए अतिरिक्त उपकरणों आदि के साथ, मोदी के नये सौदे में हरेक विमान की कीमत करीब 1,496 करोड़ रु0 बैठती है।

रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमण ने इसका वचन दिया था कि वह रफाल सौदे की वास्तविक कीमत के आंकड़े मीडिया के सामने रखेंगी। लेकिन, बाद में रक्षा मंत्री ने और मोदी

सरकार ने, इस समझौते के गोपनीयता संबंधी प्रावधान की आड़ लेकर, कहना शुरू कर दिया कि इस प्रावधान के कारण वह कीमतें बता ही नहीं सकती है। जैसाकि अनेक टिप्पणीकारों ने रेखांकित किया है, गोपनीयता का प्रावधान इस जहाज पर लगाए गए उपकरणों के वास्तविक ब्यौरों पर लागू होता है, न कि कीमत पर। फ्रांसीसी सरकार ने भी यह कहकर इस बात की पुष्टि की थी कि यह तय करना भारत सरकार पर है कि संसद को तथा देश की जनता को क्या-क्या जानकारी दे। बस वह रणनीतिक ब्यौरे जाहिर नहीं करे।

मोदी सरकार के दुर्भाग्य से दॅसां ने रफाल सौदे की वास्तविक कीमत अपनी 2017 की वित्तीय रिपोर्ट में ही उजागर कर दी थी। यह कीमत 7.4 अरब डालर या 53,870 करोड़ रु0 (1 अक्टूबर 2018 की विनिमय दर पर) है।

कीमतों संबंधी विवरण उजागर करने से सरकार के हठपूर्ण इंकार के चलते, पहले वाले सौदे और मोदी के सौदे की कीमतों में एकदम सही-सही तुलना करना तो मुश्किल होगा। फिर भी ऐसा लगता है कि नये सौदे में हरेक विमान की कीतम, पहले वाले सौदे के मुकाबले में काफी ज्यादा बैठने जा रही है।

दोनों सौदों की कीमतों की तुलना

आइटम	पुराना सौदा	नया सौदा
विमानों की संख्या	126	36
कुल कीमत	10.2 अरब डालर (74,250 करोड़) रु0	7.4 अरब डालर (53,870 करोड़) रु0
प्रति विमान कीमत	589 करोड़ रु0	1,496 करोड़ रु0

नोट: प्रति डालर 72.80 रु0 की विनिमय दर (1 अक्टूबर 2018) के आधार पर

खुले टेंडर को रद्द करने के मोदी के फैसले के लिए एचएएल को बहाना बनाया

अब जबकि नये सौदे के अंतर्गत भारत में रफाल विमान बनाए ही नहीं जाने हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न रक्षा कंपनी, एचएएल को इस सौदे से ही बाहर कर दिया गया है। कटे पर नमक छिड़कते हुए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण अब पहले वाले सौदे के रद्द किए जाने का सारा दोष एचएएल पर ही मंढने की पूरी कोशिश कर रही हैं। यह वाकई असाधारण मामला है। एचएएल, उनके ही मंत्रालय के आधीन है और जाहिर है

कि सार्वजनिक रूप से मंत्री जी के दावों का खंडन भी नहीं कर सकता है।

रक्षा मंत्री ने पिछले ही दिनों दावा किया था: अ) काम की साझेदारी और एचएएल के बनाए विमानों की गारंटियों के मुद्दे पर, दॅसां और एचएएल की वार्ताएं करीब-करीब बैठ गयी थीं; और ब) एचएएल के पास भारत में राफाल विमान बनाने की या भारतीय वायु सेना के लिए जरूरी गति से बनाने की, 'क्षमता ही नहीं थी।' इसी की वजह से सरकार को मजबूरी में पहले सौदे का उद्धार करने के लिए सामने आना पड़ा और सरकारों के स्तर पर नया समझौता करना पड़ा।

रक्षा मंत्री सीतारमण ने यह फर्जी दावा किया है कि एचएएल और दॅसां के बीच कार्य-साझीदारी समझौता बैठ गया था।

वास्तव में सरकार की ओर से अपने फैसले की 'सफाई' के तौर पर बस ये दावे ही सामने आए हैं और इनमें पहले सौदे के रद्द किए जाने का करीब-करीब सारा दोष एचएएल पर ही डाल दिया गया है।

जब पहले वाले सौदे को रद्द किया गया, दॅसां और एचएएल के बीच अंतिम कार्य साझेदारी समझौता पहले ही सरकार के हाथों तक पहुंच चुका था।

लेकिन, सवाल यह है कि अगर दॅसां तथा एचएएल के बीच बातचीत वाकई बैठ गयी थी, तो दॅसां के सीईओ, एरिक ट्रेप्पियर ने वित्तीय परिणामों पर अपनी सालाना प्रैस कान्फ्रेंस में (13 मार्च 2014 को) क्यों कहा था कि 126 राफाल लड़ाकू विमानों के लिए काम की साझेदारी पर, भारत की हिंदुस्तान एअरोनाटिक्स (एचएएल) के साथ एक पक्का समझौता हो गया है।' ट्रेप्पियर ने बताया था कि इस समझौते में, आमतौर पर विमान की संरचना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और दोनों साझीदारों के बीच काम का विस्तृत विभाजन, शामिल था। इसमें वारंटियों से सुलटने का एक तंत्र भी शामिल था। गारंटियों के मुद्दे पर समाधान यह निकला था कि दोनों पक्ष, काम के अपने-अपने दायरे की गारंटी देंगे।

टी सुवर्ण राजू ने, जो एचएएल के अध्यक्ष तथा मैनेजिंग डाइरेक्टर के पद से पिछले ही दिनों सेवानिवृत्त हुए हैं, इसकी पुष्टि की है कि दॅसां और एचएएल ने वाकई कार्य साझेदारी के समझौते पर दस्तखत कर दिए थे और यह समझौता सरकार को सौंप दिया था। उन्होंने सरकार से इसकी भी मांग की थी कि प्रासंगिक कागजात जारी कर दे, जिससे इस संबंध में सारे संदेह दूर हो जाएंगे। (*हिंदुस्तान टाइम्स,* 20 सितंबर 2018)। दूसरे शब्दों में, दोनों पक्षों के बीच कार्य साझीदारी समझौता हो गया था और गारंटियों के तंत्र पर भी सहमति हो चुकी थी। जिस समय मूल सौदे को रद्द किया गया, यह समझौता

सरकार के पास था। इसे देखते हुए यह शर्मनाक है कि रक्षा मंत्री, अपने ही मंत्रालय के आधीन चल रहे एचएएल की क्षमताओं पर सवाल खड़े कर रही हैं।

एचएएल की क्षमताएं जानी-परखी हुई हैं। 1965 के विख्यात नैट विमान या अजीत लड़ाकू विमान के मामले में उसके पहले वाले काम, देसी मारुत एचएफ-24 तथा किरण जैट ट्रेनर विमान के अलावा एचएएल ने, मिग-29 विमानों के लिए 200 अपग्रेडेड इंजन बनाए थे। वह इस समय रूस के लाइसेंस के तहत, लगभग 200 एसयू-30 एमके1 विमान, एकदम शुरूआज से बना रही है। उसने दॅसां से ही लिए गए 70 से ज्यादा मिराज-2000 विमानों में बड़े अपग्रेडेशन का काम किया है। वह ब्रिटिश एअरोस्पेस से लाइसेंस के अंतर्गत, एडवांस्ड जैट ट्रेनर विमान भी बना रही है। एचएएल ने घरेलू रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान, तेजस का उत्पादन भी शुरू कर दिया है। उसने बंगलुरु से बाहर, हैलीकोप्टर निर्माण के लिए ही समर्पित एक नया कारखाना भी खोला है, जहां सैकड़ों हैलीकोप्टर बनाए जा रहे हैं। तब भारत के रक्षा मंत्री की तो बात ही छोड़ दें, कोई भी लड़ाकू विमान बनाने की एचएएल की आजमायी हुई क्षमता पर सवाल उठा ही कैसे सकता है और वह भी तब जबकि रफाल विमान लाइसेंस के अंतर्गत या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत बनाया जाना था।

दुर्भाग्य से सत्ताधारियों ने भारतीय वायु सेना प्रमुख पर दबाव डालकर उससे ऐसे बयान दिलाए हैं, जिनमें आपूर्ति की अवधि तथा गुणवत्ता के खराब रिकार्ड के लिए और ज्यादा कीमतों के लिए भी, एचएएल की आलोचना की गयी है। यानी अपने इस फैसले के लिए सरकार अब फौजी पोशाक के पीछे छुपना चाहती है! अगर भारतीय वायु सेना और एचएएल के बीच वाकई समस्याएं थीं भी, तो क्या यह रक्षा मंत्री का ही कर्तव्य नहीं था कि इन समस्याओं का समाधान निकलवातीं? या उन्हें यही लगता है कि कर्ज के बोझ तले दबा अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप, जिसे इससे पहले का कोई अनुभव भी नहीं है, एचएएल से बेहतर विकल्प है? नये सौदे के अनुसार ये रफाल जैट भी भारत को 12 विमान प्रति वर्ष की धीमी चाल से ही मिलने वाले हैं और 2019 में तो 3 विमानों की पहली खेप ही मिलने वाली है। समझौते पर दस्तखत होने से लेकर, इन 36 विमानों की आपूर्ति के पूरे होने तक, दॅसां पूरे 6 साल लगा चुकी होगी।

तब एचएएल विमान आपूर्ति की धीमी रफ्तार का इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? इससे पहले भारतीय वायु सेना द्वारा हर साल 12 तेजस विमान ही देने के लिए एचएएल की आलोचना की जा रही थी। इन विमानों की

अगर एचएएल की आपूर्ति की रफ्तार से वाकई समस्या थी, तो दॅसां को 36 विमानों की आपूर्ति के लिए छः साल का समय क्यों दिया गया?

आपूर्ति बढ़ाकर अब प्रति वर्ष 18 कर दी गयी है। जाहिर है कि यह एचएएल द्वारा बाकी जो सब कुछ किया जा रहा है, उसके ऊपर से है।

यह बिल्कुल साफ है कि सरकार, पहले के सौदे को रद्द करने एक नये सौदे पर दस्तखत करने के अपने, किसी भी तरह से सही न ठहराए जा सकने वाले कदम के लिए बहाना बना रही है। अब साफ हो गया है कि यह नया सौदा, रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में नये-नये आये निजी खिलाड़ी, अनिल अंबानी के लिए बेहिसाब फायदा पक्का करेगा।

अप्रत्याशित साझीदार के रूप में अनिल अंबानी की रिलायंस का पदार्पण

इस टेंडर में इसका प्रावधान है कि ठेके की कुल कीमत का 50 फीसद, ऑफसैट्स के जरिए भारत में ही खर्च किया जाएगा। ''आफसैट'' के इस प्रावधान के अनुसार, दॅसां को रफाल सौदे की कुल कीमत के 50 फीसद के बराबर राशि, भारत में ही खर्च करनी होगी। बेशक, ऑफसैट्स के प्रावधान का लक्ष्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि रक्षा खरीद के खर्चे का एक खासा बड़ा हिस्सा अपने देश में ही बनाए रखा जाए। इसका मकसद यह भी है कि घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षमता को मजबूत किया जाए, देश के रक्षा औद्योगिक आधार को व्यापक बनाया जाए और उन्नत प्रौद्योगिकीय ज्ञान देश में लाया जाए।

मोदी के मूल सौदे को निरस्त करने के सिर्फ 12 दिन पहले रिलायंस डिफेंस लि0 को इन्कार्पोरेट कराया गया था।

इस लिहाज से तिथियों का क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेरिस में मूल सौदे के निरस्त किए जाने से सिर्फ 12 दिन पहले, 28 मार्च 2015 को रिलायंस एडीएडी ने, रिलायंस डिफेंस लि0 नाम से एक नयी कंपनी रजिस्टर करायी। 10 अप्रैल 2015 को मोदी ने 126 विमानों के मूल सौदे को रद्द कर दिया और 36 विमानों के नये सौदे पर दस्तखत कर दिए। जब मूल सौदे को रद्द किया गया और एक नये समझौते पर दस्तखत किए गए, अनिल अंबानी वहीं, पेरिस में ही थे। पुनः, पेरिस समझौते पर दस्तखत होने के 13 दिन बाद ही, रिलायंस डिफेंस लि0 की सब्सीडियरी, रिलायंस एअरोस्ट्रक्चर लि0 की स्थापना की गयी। अब हमसे यह मान लेने के लिए कहा जा रहा है कि ये तारीखें और घटनाएं, महज संयोग की वजह से ही आपस में जुड़ी नजर आती हैं।

अपने सिर पर 1 लाख करोड़ रु0 से ज्यादा का कर्जा लदा होने के बावजूद, रिलायंस 20,000 करोड़ रु0 के ऑफसैट्स का ठेका दिलाया गया है।

नये सौदे के अंतर्गत रिलायंस एअरोस्ट्रक्चर लि0, जोकि भारी कर्ज में डूबे रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का हिस्सा है, जिस पर 1 लाख करोड़ रु0 की दबाव में आयी परिसंपत्तियों का बोझ है, दॅसां का मुख्य ऑफसैट साझीदार होगी। रिलायंस के इस ऑफसैट ठेके का कुल मूल्य करीब 20,000 करोड़ रु0 बैठेगा, जबकि बाकी करीब 9,000 करोड़ रु0 के ठेके अन्य भारतीय साझीदारों में बांटे जा रहे हैं। ऑफसैट्स की कुल राशि, रफाल सौदे के कुल मूल्य के 50 फीसद के बराबर होगी।

पुनः, चूंकि नया सौदा तैयारशुदा 36 रफाल विमानों की खरीद का है, इस सौदे के संबंध में दॅसां के आफसैट आधारित काम का जो रिलायंस डिफेंस को दिया गया है, रफाल विमानों से कुछ लेना-देना ही नहीं है। खबरों के अनुसार उसे दॅसां के ही फॉल्कन एक्जिक्यूटिव जैट विमानों के कुछ कल-पुर्जे बनाने का ही काम दिया जा रहा है।

क्या इस पर यकीन किया जा सकता है कि इतने विशाल सौदे में, ऑफसैट्स साझीदार के चुनाव में सरकार की कोई भूमिका ही नहीं थी।

रिलायंस ग्रुप अगर विनिर्माण के किसी भी अनुभव का दावा कर सकता है, तो इसी के आधार पर कि उसने 2016 की जनवरी में पिपावाव शिपयार्ड का अधिग्रहण किया था। लेकिन, यह अधिग्रहण भी रिलायंस डिफेंस सिस्टम्स प्राइवेट लि0 द्वारा किया गया था, जो रिलायंस डिफेंस लि0 से अलग कंपनी है।

रिलायंस के चयन का फैसला किस का था ?

रक्षा मंत्री और सरकार के दूसरे प्रवक्ता बार-बार इसके दावे कर रहे हैं कि कर्ज से दबे रिलायंस एडीएजी को ऑफसैट साझीदार के रूप में चुनने का फैसला, स्वतंत्र रूप से दॅसां द्वारा लिया गया था और भारत सरकार का इससे कुछ लेना-देना ही नहीं था। याद रहे कि रिलायंस एडीएजी की चार फ्लैगशिप कंपनियों—रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, रिलायंस कैपीटल लि0, रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि0 तथा रिलायंस पॉवर—के खातों में, कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रु0 का ऋण दर्ज है।

इसलिए, इसे अचरज की बात कहा जाएगा कि दॅसां जैसी विशालकाय तथा प्रतिष्ठित कंपनी, अपने ही विवेक से एक ऐसी कंपनी को ऑफसैट्स साझीदार के तौर पर चुनेगी, जो पूरी तरह से अनुभवहीन है और विमानन के क्षेत्र में, वास्तव में विनिर्माण के क्षेत्र में ही, एकदम नयी-नयी आयी है। यह भी एक जानी-मानी बात है कि ऐसे भारी-भरकम शस्त्र खरीद के सौदों के मामले में, दोनों देशों में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की निश्चित भूमिका रहती है और लाइसेंस के तहत विनिर्माण या ऑफसैट्स के मामलों में, खरीददार

सरकार की आफसैट्स साझीदार के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि भारत सरकार ने आफसैट्स को लेकर सारी बातचीत से पूरी तरह से अपने हाथ खींच लिए होंगे और दॅसां पर ही छोड़ दिया होगा कि वह अपनी मर्जी से किसी को भी साझीदार बना ले।

इस मामले में भारत सरकार के दावों अब और किसी ने नहीं, खुद फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति, फ्रांस्वा ओलांद ने खंडन कर दिया है। फ्रांसीसी ऑन लाइन खोजी तथा विचारों की वैबसाइट, मीडियापार्ट को दिए गए साक्षात्कार में, इस प्रश्न के उत्तर में कि रिलायंस को कैसे तथा किसने चुना था, ओलांद ने कहा है: *'उसमें हमारा कोई दखल नहीं था। भारत सरकार ने ही इस सर्विस ग्रुप (रिलायंस) का प्रस्ताव किया था और दॅसां ने अंबानी से वार्ता की थी। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हमें जो संभाषी दिया गया, हमने उसे ही मंजूर कर लिया।'*

ओलांद ने इस झूठ के धुर्रे बिखेर दिए कि दॅसां ने खुद रिलायंस को चुना था: 'हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हमें जो संभाषी दिया गया, हमने उसे ही मंजूर कर लिया।'

ओलांद ने फ्रांसीसी समाचार एजेंसी, एएफपी से बात करते हुए, 22 सितंबर को अपनी बात को और साफ कर दिया। 'श्री ओलांद ने कहा कि रिलायंस ग्रुप का नाम, रफाल सौदे के लिए वार्ताओं में एक ''नये फार्मूले'' के हिस्से के तौर पर आया था, जो सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने तय किया था।'

मोदी सरकार के शीर्ष अधिकारी बड़ी कसरत से इसका दावा करते आए हैं कि भारत सरकार का, दॅसां के ऑफसैट ठेकों से कुछ लेना-देना ही नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नये सौदे का एलान किए जाने के साल भर से ज्यादा बाद में और अंतिम समझौते पर दस्तखन होने से चंद महीने पहले, 2015 के अगस्त में, रक्षा मंत्रालय ने ऑफसैट्स संबंधी दिशानिर्देशों में एक संशोधन किया था। इस संशोधन के जरिए विदेशी विक्रेताओं को इसकी इजाजत दे दी गयी कि वे, सौदे पर दस्तखत होने की तारीख के बाद, अपने भारतीय ऑफसैट्स साझीदार के संबंध में रक्षा मंत्रालय को विवरण दे सकते हैं। मोदी सरकार इसी प्रावधान की आड़ लेकर, यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि रफाल सौदे में दॅसां के ऑफसैट्स साझीदार के बारे में उसे तो कुछ पता ही नहीं था।

बहरहाल, 2013 तथा 2016 के डिफेंस प्रोक्योरमेंट पर्चेज (डीपीपी) दस्तावेज के अनुसार, जिसमें आफसैट के दिशानिर्देश सूत्रबद्ध किए गए हैं, दूसरे ऐसे प्रावधान हैं जो इसका तकाजा करते हैं कि सौदे के अंतिम रूप से तय होने से पहले, बोली लगाने वाले को वार्ता कमेटी को अपने आफसैट कांट्रैक्ट का पूरा विवरण देना होगा। *कारवां* पत्रिका ने

अपने 2018 के सितंबर के अंक में रफाल सौदे पर जो कवर स्टोरी की है, उसमें बताया गया है कि इस पत्रिका की एक आरटीआइ के जवाब में, वायु सेना मुख्यालय ने इसकी पुष्टि की थी कि दो सरकारों के बीच समझौते और सरकार तथा दॅसां के बीच आफसैट समझौते, दोनों पर एक ही दिन दस्तखत किए गए थे—23 सितंबर 2016 को। अगर रक्षा मंत्रालय को सचमुच दॅसां के आफसैट साझीदार के बारे में पता ही नहीं था, तो यह 2013 के डीपीपी के उल्लंघन का मामला होगा। कहीं सरकार जनता से झूठ तो नहीं बोल रही है कि जब उसने सौदे पर दस्तखत किए थे, उसे पता ही नहीं था कि दॅसां का ऑफसैट साझीदार कौन है?

सरकारों के बीच हुए रफाल सौदे और दॅसां तथा भारत सरकार के बीच ऑफसैट समझौते पर, एक ही दिन दस्तखत हुए थे—23 सितंबर 2016 को।

अब तक हम जो कुछ देख चुके हैं, उसके आधार पर हम इतना अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि आने वाले कुछ ही अर्से में इस भाजपा सरकार के और कई घोटाले सामने आने वाले हैं। राफाल सौदा, मोदी सरकार के लिए बोफोर्स प्रकरण जैसा साबित हो सकता है।

यह पहली बार ही था कि प्रधानमंत्री ने खुद सीधे हस्तक्षेप कर, पहले वाले रक्षा सौदे को रद्द किया था और एक नये सौदे पर मोहर लगायी। और यह सब रक्षा खरीद के सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए और किसी से भी, यहां तक कि खुद वायु सेना से भी, परामर्श या चर्चा के बिना ही किया गया था। इससे पहले कभी इस देश में ऐसा नंगा दरबारी पूंजीवाद देखने को नहीं मिला था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रक्षा सौदे में अनिल अंबानी को आगे बढ़ाया गया है, जिसकी कंपनियों को इसका कोई अनुभव ही नहीं है और जिसके कारोबारी साम्राज्य पर 1 लाख करोड़ रु0 से ज्यादा का कर्जा है।

इस मामले में सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री से ही शुरू होती है और उन पर ही खत्म होती है। उन्होंने ही व्यक्तिगत रूप से और सीधे, सब कुछ तय किया था।

इसके अलावा हमारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, जिन्हें झूठ बोलने में या रक्षा क्षेत्र की एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी को बदनाम करने में कोई हिचक नहीं हुई है। और उन्होंने ऐसा कोई देश के हित के लिए नहीं बल्कि अपने नेता तथा अनिल अंबानी के कारोबारी साम्राज्य के हित के लिए ही किया है।

सी पी आइ (एम) और अनेक विपक्षी पार्टियां इसकी मांग कर रही हैं कि एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए, ताकि इस सौदे की तथा इसमें प्रधानमंत्री की भूमिका की जांच की जा सके। हम जनता का आह्वान करते हैं कि इस मांग को अपना समर्थन दे

और बदतरीन किस्म के दरबारी पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री पद के इस दुरुपयोग को और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ को बेनकाब करें।

रफाल सौदा—घटनाक्रम	
2004	रिक्वेस्ट फॉर इन्फार्मेशन (आरएफआइ) जारी किए जाने के साथ, 126 मल्टी रोल कंबैट एअरक्राफ्ट (एमआरसीए) के लिए टेंडर की शुरूआत हुई।
2007	अंतिम आरएफपी में वांछित विमान श्रेणी को बदलकर मीडियम वेट मल्टीरोल कंबैट एअरक्राफ्ट (एमएमआरसीए) कर दिया गया।
2012	कड़े मैदानी परीक्षणों तथा विमान के जीवन चक्र दामों की तुलना करने के बाद, दॅसां के रफाल विमान को चुन लिया गया।
28 मार्च 2015	रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने रिलायंस डिफेंस लि0 के नाम से नयी सब्सीडियरी रजिस्टर करायी।
10 अप्रैल 2015	पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी ने 126 विमानों के टेंडर को रद्द करने और उसकी जगह पर 36 पूरी तरह से तैयार रफाल विमान खरीदने का एलान किया जो पूरी तरह से फ्रांस में दॅसां द्वारा बनाए जाएंगे। मोदी की इस यात्रा के दौरान अनिल अंबानी पेरिस में थे।
24 अप्रैल 2015	पेरिस समझौते के 13 दिन बाद ही, रिलायंस डिफेंस लि0 की सब्सीडियरी, रिलायंस एअरोस्ट्रक्चर लि0 की स्थापना कर दी गयी।
23 सितंबर 2016	भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्रियों ने दॅसां से 36 रफाल विमान खरीदने के समझौते पर दस्तखत किए। उसी रोज दॅसां और भारत सरकार के बीच ऑफसैट समझौते पर दस्तखत हुए।
3 अक्टूबर 2016	रिलायंस एअरोस्ट्रक्चर और दॅसां एविएशन से, क्रमश: 51 तथा 49 फीसद की साझेदारी के साथ, एक संयुक्त उद्यम कायम किया।